

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
07.08.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2720 का उत्तर

कल्लाकुरिची में जारी परियोजनाओं और अतिरिक्त कनेक्टिविटी को पूरा करना

2720. श्री मलैयारासन डी.:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राज्य और केन्द्र सरकार के वित्तीय योगदान से चिन्नासेलम से कल्लाकुरिची तक नई रेल लाइन का निर्माण वर्ष 2016 से धीमी गति से चल रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे;
- (ग) इस वर्ष थियागाडुरुगम, थिरुकोइलुरे डिरोमग के रास्ते 60 कि.मी. तक कल्लाकुरिची से मुगैयूर रेलवे स्टेशन तक रेल लाइन के विस्तार के लिए निधियां आवंटित करने के लिए सरकार की क्या कार्य-योजना है; और
- (घ) सेलम और तिरुवन्नामलाई को कल्लाकुरिची और कल्लाकुरिची के रास्ते उलुन्दुरपेट से जोड़ने के लिए एक नई रेल लाइन प्रदान करने के संबंध में सरकार की आगे की योजना क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

कल्लाकुरिची में जारी परियोजनाओं और अतिरिक्त कनेक्टिविटी को पूरा करने के संबंध में दिनांक 07.08.2024 को लोक सभा में श्री मलैयारासन डी. के अतारांकित प्रश्न सं. 2720 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेल परियोजनाएं क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत और शुरू की जाती हैं, न कि राज्य-वार क्योंकि भारतीय रेल की परियोजनाएं विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। बहरहाल, 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली 33,467 करोड़ रुपए की लागत से 2,587 कि.मी. कुल लंबाई की 22 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (10 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 09 दोहरीकरण) योजना/स्वीकृति/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 665 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 7,153 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

14,669 करोड़ रुपए की लागत पर 872 कि.मी. कुल लंबाई की 10 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से 24 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 1,223 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

5,417 करोड़ रुपए की लागत पर 748 कि.मी. कुल लंबाई की 03 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिनमें से 604 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 3,267 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

13,381 करोड़ रुपए की लागत पर 967 कि.मी. लंबाई की 09 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें से 37 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 2,664 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

चिन्नसेलम - कल्लाकुरिची (16 कि.मी.) नई लाइन को रेलवे और तमिलनाडु राज्य सरकार के बीच लागत में 50:50 भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 99 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। उपलब्ध भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी क्लीयरेंस, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूगर्भीय और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष के दौरान कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के समापन समय को प्रभावित करते हैं। उपर्युक्त अवरोधों के बावजूद, परियोजना/परियोजनाओं को तेजी से निष्पादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

चिन्नसेलम - कल्लाकुरिची नई लाइन परियोजना के पूरा होने पर वृद्धाचलम के रास्ते से कल्लाकुरिची और मुगैयूर के बीच संपर्कता की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, तिरुक्कोविलुर भारतीय रेल नेटवर्क पर एक मौजूदा स्टेशन है। थीयागदुर्गम के रास्ते कल्लाकुरिची - मुगैयूर की नई रेल लाइन पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।

सेलम पहले से ही विलुप्पुरम और वृद्धाचलम के रास्ते तिरुवन्नामलाई और उलुंदूरपेट से जुड़ा हुआ है। चिन्नसेलम - कल्लाकुरिची नई लाइन परियोजना के पूरा होने पर सेलम और तिरुवन्नामलाई के बीच संपर्कता की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कल्लाकुरिची और तिरुवन्नामलाई (69 किमी) के बीच एक सर्वेक्षण को स्वीकृति दी गई है।

रेल अवसंरचना परियोजनाएं लाभप्रदता, अंतिम छोर तक संपर्क, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, सामाजिक-आर्थिक महत्व, आदि के आधार पर शुरू की जाती हैं जो चालू परियोजनाओं की देयताओं, निधियों की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है।

2014 से, तमिलनाडु राज्य में परियोजनाओं की निधि आबंटन और तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि निम्नानुसार है:-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आबंटन के संबंध में वृद्धि
2009-14	₹879 करोड़/वर्ष	-
2023-24	₹6,080 करोड़	6 गुना से अधिक
2024-25	₹6,362 करोड़	7 गुना से अधिक

यद्यपि निधि आबंटन में कई गुना वृद्धि हुई है परन्तु परियोजना के निष्पादन की गति शीघ्र भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है।

रेलवे द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मुआवजे की राशि का आकलन किया जाता है और इस संबंध में रेलवे को सूचित किया जाता है। राज्य सरकार से मांग प्राप्त होने पर, रेलवे द्वारा मुआवजा राशि संबंधित जिला भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण को जमा कराई जाती है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है और लगभग 2749 हेक्टेयर की कुल आवश्यक भूमि में से केवल लगभग 807 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयास शुरू किए थे परन्तु परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहीत करने में सफल नहीं हो सका।

भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।
